भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
10.12.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1751 का उत्तर

शिवमोगा में रेलवे लाइन

1751. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिवमोगा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णतः या आंशिक रूप से आने वाली निम्नलिखित नई रेल लाइन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और उनसे संबंधित मूल लक्ष्य प्राप्त करने की तिथियाँ और परियोजना-वार संशोधित अपेक्षित समय-सीमा क्या है;

(i) शिवमोगा - शिकारीपुरा - रानेबेन्नूर नई लाइन (लगभग 103 कि.मी.),

(ii) शिवमोगा - हरिहर नई लाइन (लगभग 79 कि.मी.)।

(ख) कर्नाटक राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण स्वीकृति में विलंब के क्या कारण हैं और अपेक्षित भूमि, अधिगृहीत भूमि एवं अधिगृहीत की जाने वाली शेष भूमि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे द्वारा राज्य सरकार से मांगी गई धनराशि और आज की तिथि तक राज्य सरकार द्वारा वास्तव में जमा की गई धनराशि के ब्यौरे सहित दोनों परियोजनाओं हेतु लागत-साझाकरण समझौते की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण स्वीकृति और समय पर समापन सुनिश्चित करने वाले राज्य के वित्तीय योगदान में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए या प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): शिवमोगा-शिकारीपुरा-राणिबेन्नूरु नई लाइन परियोजना (79 कि.मी.) को 50:50 लागत भागीदारी आधार और कर्नाटक सरकार द्वारा नि:शुल्क भूमि मुहैया कराए जाने पर

स्वीकृत की गई है। कुल 559 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 226 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है और शेष 333 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना बाकी है।

शिवमोगा-हरिहर नई लाइन परियोजना (79 कि.मी.) को 50:50 लागत भागीदारी आधार और कर्नाटक सरकार द्वारा नि:शुल्क भूमि मुहैया कराए जाने पर स्वीकृत की गई है। रेलवे ने कर्नाटक सरकार को परियोजना के लिए संपूर्ण 488 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत करने का अनुरोध किया था। बहरहाल, कर्नाटक सरकार ने लागत भागीदारी करने और नि:शुल्क भूमि मुहैया कराने में अपनी असमर्थता व्यक्ता की है। इस कारण परियोजना रूकी हुई है।

<u>कर्नाटक:</u>

हाल के वर्षों में बजट आबंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। कर्नाटक राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	₹835 करोड़ प्रति वर्ष
2025-26	₹7,564 करोड़ (9 गुना से अधिक)

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली वाली ₹42,517 करोड़ की लागत से 3,264 किलोमीटर लंबाई की 25 परियोजनाएं (15 नई लाइनें, 10 दोहरीकरण) स्वीकृत की गई हैं। सारांश निम्नानुसार है:-

कोटि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च 2025 तक कमीशन की गई लंबाई (किमी)	मार्च, 2025 तक व्यय (₹ करोड़ में)
नई लाइन	15	2,034	421	8,794
दोहरीकरण/बहुपथन	10	1,230	973	12,516
कुल	25	3,264	1,394	21,310

कर्नाटक में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली तथा हाल ही में पूरी की गई कुछ परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1	कोत्तूर-हरिहर नई लाइन (65 किलोमीटर)	468
2	हासन-बेंगलोर नई लाइन (167 किलोमीटर)	1290
3	बीदर-गुलबर्गा नई लाइन (110 किलोमीटर)	1543
4	शिवानी-होसदुर्ग रोड दोहरीकरण (10 किलोमीटर)	50
5	शिवानी-बिरुर दोहरीकरण (29 किलोमीटर)	143
6	होसदुर्ग-चिकजाजुर दोहरीकरण (29 किलोमीटर)	260
7	रामनगरम-मैसूर कहीं-कहीं दोहरीकरण (94 किलोमीटर)	998
8	यलहंका-चन्नासंद्रा दोहरीकरण (13 किलोमीटर)	108
9	यशवंतपुर-यलहंका दोहरीकरण (12 किलोमीटर)	95
10	नेत्रावती-मंगलौर सेंट्रल दोहरीकरण (2 किलोमीटर)	28
11	कन्कनाडि-पनम्बूर दोहरीकरण (19 किलोमीटर)	350
12	अरसीकेरे-तुमकुर दोहरीकरण (96 किलोमीटर)	758
13	यलहंका-पेनुकोंडा दोहरीकरण (123 किलोमीटर)	1104
14	दौंड-गुलबर्गा दोहरीकरण (225 किलोमीटर)	3182
15	हुबली-चिकजाजुर दोहरीकरण (190 किलोमीटर)	1850

कर्नाटक में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुछ परियोजनाएं, जो शुरू की गई हैं, निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1	होसपेट-हुबली-लोंडा-वास्को-द-गामा दोहरीकरण (312 किलोमीटर)	4153
2	होटगी-गदग दोहरीकरण (284 किलोमीटर)	2459
3	गिणिगेरा - रायचूर नई लाइन (165 किलोमीटर)	3401
4	गदग - वाडी नई लाइन (257 किलोमीटर)	2842
5	बागलकोट - कुडची नई लाइन (142 किलोमीटर)	1649
6	तुमकुर - चित्रदुर्ग-रायदुर्ग नई लाइन (207 किलोमीटर)	2496
7	तुमकुर - दावणगेरे नई लाइन (182 किलोमीटर)	2142
8	कडूर - चिकमगलूर-बेलूर नई लाइन (68 किलोमीटर)	825
9	बैयप्पनहल्ली - होसुर दोहरीकरण (48 किलोमीटर)	336
10	यशवंतपुर - चन्नासंद्रा दोहरीकरण (22 किलोमीटर)	314

पिछले तीन वर्षों 2022-23, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष 2025-26 में, कर्नाटक राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुल 7,239 किलोमीटर लंबाई को कवर करने वाले 65 सर्वेक्षण कार्यों (25 नई लाइन और 40 दोहरीकरण) को स्वीकृति दी गई है।

भूमि अधिग्रहण के कारण लंबित कुछ प्रमुख परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है: -

क्र. सं.	परियोजना	अपेक्षित कुल भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत की गई भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत किए जाने हेतु शेष भूमि (हेक्टेयर में)
1	शिमोगा- राणिबेन्नुर नई लाइन (96 किलोमीटर)	559	226	333
2	बेलगाम - धारवाड नई लाइन (73 किलोमीटर)	581	0	581
3	शिमोगा - हरिहर नई लाइन (79 किलोमीटर)	488	0	488
4	व्हाइटफील्ड-कोलार नई लाइन (53 किलोमीटर)	337	0	337
5	हासन-बेलूर नई लाइन (27 किलोमीटर)	206	0	206

कर्नाटक में भूमि अधिग्रहण की स्थिति का सारांश इस प्रकार है:-

कर्नाटक में परियोजनाओं के लिए अपेक्षित कुल भूमि	9020 हेक्टेयर
अधिगृहीत भूमि	5679 हेक्टेयर (63%)
अधिगृहीत की जाने वाली शेष भूमि	3341 हेक्टेयर (37%)

भारत सरकार परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए तैयार है, बहरहाल सफलता पश्चिम कर्नाटक के सहयोग पर निर्भर करती है।

किसी भी रेल परियोजना की स्वीकृति कई मानदंडों/कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रत्याशित यातायात पूर्वानुमान और प्रस्तावित मार्ग की लाभप्रदता
- परियोजना द्वारा प्रदान की गई पहली और अंतिम छोर तक संपर्कता

- अनुपलब्ध कड़ियों को जोड़ना और अतिरिक्त मार्ग प्रदान करना
- संकुलित/संतृप्त लाइनों का आवर्धन
- राज्य सरकारों/केंद्रीय मंत्रालयों/जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगें
- रेलवे की अपनी परिचालन संबंधी आवश्यकताएँ
- सामाजिक-आर्थिक महत्व
- निधियों की समग्र उपलब्धता

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण
- वन संबंधी मंजूरी
- अतिलंघनकारी जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरियाँ
- क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक स्थिति
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति
- परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने वाले महीनों की संख्या आदि

ये सभी कारक परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

*****